फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 117 प्रभात जयपुर, शनिवार 28 नवम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBiT



A Piece Of Collectible Art

He just started picking up old radios from random sources and replacing the inner circuits with locally available Bluetooth speakers until he ran short of radios

The Hidden Meaning Behind the Rhythmic Syllables

डीलिमिटेशन पर बहस काफी क्रोधपूर्ण व कटुता युक्त होगी संसद में

पर, इसके बावजूद, भाजपा यह विधेयक पारित करा लेगी सदन में

- जब राहुल गांधी को इस तथ्य से अवगत कराया गया तो उन्होंने जोशीला जवाब दिया, चाहे सदन में हमारे सांसदों की संख्या कुछ भी हो, हम इस विधेयक का पूरे जोर से विरोध करेंगे।
- तमिलनाडु सबसे पहले डीलिमिटेशन का विरोध करने वालों में से था। पर, राहुल गांधी ने स्वयं तमिलनाडु में डीएमके का साथ छोड़कर, विजय की पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन किया। राहुल गांधी से बदला लेने की दृष्टि से स्टालिन अब डीलिमिटेशन के मुद्दे पर मोदी के साथ व समर्थन में खड़े हैं। हालांकि, वे जानते हैं कि डीलिमिटेशन उनके लिए घातक साबित हो सकता है।
- डीलिमिटेशन के बाद, तमिलनाडु में सांसदों की संख्या चालीस से बढ़कर साठ हो जाएगी तथा यूपी में निर्वाचित सांसदों की संख्या 80 से बढ़कर 120 हो जाएगी।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। नरेन्द्र मोदी सरकार परिसीमन विधेयक (डीलिमिटेशन बिल) पारित कराने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। इसमें सरकार को शरद पवार की एनसीपी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस के उन 20 गैर-मान्यता प्राप्त सांसदों, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, और कुछ अन्य छोटे दलों के सांसदों का समर्थन मिल सकता है।

अमित शाह इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में पूरी ताकत से लगे हुए हैं।

कांग्रेस ने आज शाम अपनी रणनीति पर चर्चा के लिए एक बैठक की और मतदान पर चर्चा करने के लिए कल सुबह इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक होगी।

बताया जाता है कि राहुल गांधी ने कहा है कि वे इस विधेयक का पूरी ताकत से विरोध करेंगे, लेकिन भाजपा इसका राजनीतिक फायदा उठाना और राजनीतिक अंक हासिल करना चाहती है। जयराम रमेश ने बैठक में सांसदों की संख्या का पूरा ब्योरा दिया, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि संख्या चाहे जो भी हो, कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी।

सबसे पहले डीएमके ने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर आपत्ति जताई थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा डीएमके का साथ छोड़कर विजय की टीवीके के साथ गठबंधन करने के फैसले के फलस्वरुप, स्टालिन अब राहुल गांधी और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए मोदी का समर्थन कर रहे हैं।

हालाँकि वे भली भाँति जानते हैं कि परिसीमन दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राजनीतिक दलों के लिए अस्तित्व का संकट बन सकता है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। यह एनसीपी और डीएमके की मांग थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की कुल 40 सीटें बढ़कर 60 हो जाएंगी, जबकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बढ़कर 120 हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि इससे तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों को कितना नुकसान होगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लोकसभा सीटें 50 प्रतिशत बढ़ने की संभावना

नई दिल्ली, 27 नवंबर। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में केन्द्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

इसी को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सेवातीर्थ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक हुई।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में परिसीमन विधेयक को मंजूरी दी गई

- केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने परिसीमन विधेयक को मंजूरी दी।

है। इसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक बढ़ ोतरी की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, विधेयक में सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए साल 2011 की जनगणना को आधार बनाने का प्रावधान किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव का उद्देश्य परिसीमन के बाद किसी भी राज्य की राजनीतिक हिस्सेदारी कम होने की आशंका को दूर करना है।

इसके साथ ही राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के मौजूदा अनुपात को वर्ष 2051 तक स्थिर रखने का प्रस्ताव भी किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि 30 नवंबर से लोकसभा और 2 दिसंबर से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। 3 दिसंबर को सत्रावसान होगा।

बाँग्लादेश के स्पीकर की बयानबाजी से तनाव फैला व अचम्भा हुआ

स्पीकर हाफिज़उद्दीन अहमद ने, 1971 के बाँग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका पर सवाल उठाए

- स्पीकर महोदय का कहना था कि भारत की बाँग्लादेश की आज़ादी में कोई रूचि नहीं थी। भारत तो पाकिस्तान के दो टुकड़े करवाने और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की दृष्टि से "मुक्ति आंदोलन" में कूदा था।
- मजे की बात यह भी है कि स्पीकर हाफिज़उद्दीन अहमद प्रारम्भ में पाकिस्तान की सेना के कैप्टन थे, "मुक्ति आंदोलन" से जुड़ने से पहले तथा बाँग्लादेश के "मुक्ति आंदोलन" में प्रशंसनीय भूमिका निभाने पर उन्हें बाँग्लादेश का प्रतिष्ठित अवॉर्ड, "बीर बिक्रम" पुरस्कार भी मिला था।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। बांग्लादेश की संसद के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद ने 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका पर सवाल उठाकर, कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन करके और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में बने रहने को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्यवाही की चेतावनी देकर दक्षिण एशिया में कूटनीतिक बेचैनी पैदा कर दी है।

23 से 29 नवंबर तक अपनी संसदीय यात्रा के दौरान इस्लामाबाद में दिए गए अहमद के ये बयान, ढाका की पिछली सरकारों द्वारा भारत-पाकिस्तान के मुद्दों पर बरती जाने वाली पारंपरिक संयम की नीति से बिल्कुल अलग हैं। सन् 1971 में, भारत की भूमिका को देखते हुए बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर उनकी टिप्पणियां विशेष रूप से संवेदनशील हैं।

पाकिस्तान के संसद भवन में पत्रकारों से बात करते हुए अहमद ने कहा कि भारत ने 1971 में बंगालियों की मदद नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की थी। उनका यह दावा ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई से बचकर भागे करीब एक करोड़ शरणार्थियों को भारत ने शरण दी थी।

यह युद्ध 16 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। पिछले पांच दशकों से अधिक समय से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में भारत का योगदान अहम रहा है।

अहमद ने आरोप लगाया कि शेख हसीना के 15 साल के शासनकाल में बांग्लादेश एक "भारतीय उपनिवेश" बन गया था। इसके साथ ही, उन्होंने नई दिल्ली पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा ने बड़ी होशियारी से विपक्ष के "डीलिमिटेशन" के विरोध को नाकाम किया

विपक्ष के कुछ दलों की आशंकाओं को शांत किया अपने तर्कों से

- कुछ को राजनीतिक सौदेबाज़ी से, विरोध की जिद छोड़ने की प्रेरणा दी।
- पर, यह भी सच है, भाजपा ने अपने राजनीतिक हितों को सर्वोच्च नहीं मान कर, काफी लचीलेपन का रवैया रखा।

-श्रीनंद झा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। विशेष संसद सत्र में परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सरकार की नई कोशिश का विरोध करने की इंडिया गठबंधन की रणनीति अभी स्पष्ट नहीं है। डीएमके, और शरद पवार की एनसीपी सहित, कुछ क्षेत्रीय दलों द्वारा इस विधेयक का समर्थन करने के संकेत मिल रहे हैं।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 27 नवंबर को संशोधित विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में एक समान 50 प्रतिशत बढ़ोतरी और राज्यों के बीच मौजूदा सीटों के अनुपात (जो वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है) को 2051 तक यथावत् बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। इससे तमिलनाडु सहित, दक्षिण भारत के राज्यों की चिंताओं का समाधान होने की संभावना है।

इस विधेयक को संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। संसद का यह विशेष सत्र 30 नवम्बर से लोकसभा में तथा 2 दिसम्बर से राज्यसभा में शुरु होने जा रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बडोदरा के पास जैश का आतंकी गिरफ्तार

वडोदरा, 27 नवंबर। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। उसे हालोल-वडोदरा हाईवे पर गोल्डन चौकड़ी के पास से पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक एके-47 राइफल और 23

- उसके पास एके -47 राइफल और 23 जिंदा कारतूस मिले।

जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने के इरादे से आया था। आरोपी की पहचान असम के करीमगंज जिले के मूल निवासी मोहम्मद शाहरुख इस्लाम कबीरूद्दीन के रूप में हुई है। उसके मदरसे में पढ़ाई करने की जानकारी भी सामने आई है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक, वह असम से ट्रेन के जरिए भोपाल और फिर वहां से बस से वडोदरा पहुंचा था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अखिलेश यादव इतनी जल्दबाजी में क्यों है, यूपी के चुनाव की तैयारी में?

उनका मानना है कि गठबंधन (सीटों का बंटवारा आदि) फाइनल करने में जितना विलंब होगा, उससे गठबंधन में मतभेद की चर्चाओं से दोनों पार्टियों (सपा व कांग्रेस) की सार्वजनिक छवि को उतनी ही हानि होगी

- इसीलिए, उन्होंने पाँच सीटों पर अपने उम्मीदवारों की एकतरफा घोषणा कर कांग्रेस पर दबाव बनाने का प्रयास किया है।

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मुकाबले की तस्वीर लगभग तय होती दिखाई दे रही है। राज्य में एनडीए, इंडिया गठबंधन और छोटे सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के संभावित तीसरे मोर्चे के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। हालांकि, राजनीतिक समीकरण अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन, समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी एजेंडा तय करने में शुरुआती बढ़त बना ली है। उन्होंने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है और अपनी चुनावी टीम को सक्रिय कर दिया है।

अखिलेश यादव की रणनीति में सबसे खास बात उनकी तैयारियों की तेज रफ्तार है। सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। दोनों पार्टियां कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। गठबंधन की ओर से मतदाताओं से किये जाने वाले बड़े वादों और चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है। इसके बावजूद, अखिलेश बातचीत पूरी होने का इंतजार किए बिना अपनी तैयारियों में जुट गए हैं।

उनके इन शुरुआती कदमों ने राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा छेड़ दी है। क्या यह उनके बढ़े हुए आत्मविश्वास का संकेत है? या फिर सपा प्रमुख जानबूझकर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कांग्रेस की वजह से उनकी चुनावी तैयारियां प्रभावित न हों?

राजनीतिक जानकारों और सूत्रों के अनुसार, अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में नए आत्मविश्वास के साथ उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव और हाल ही में हुए बिहार में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के अनुभव से भी सबक लिया है।

अखिलेश यादव के नए आत्मविश्वास के पीछे सबसे बड़ा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई पेपर लीक का दो साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

जयपुर, 27 नवम्बर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में दो साल से फरार चल रहे दस हजार रुपए के इनामी आरोपी श्रीराम विश्नोई उर्फ अतुल विश्नोई को गिरफ्तार किया है। आरोपी जगदीश विश्नोई ओमप्रकाश ढाका गिरोह का

- एसओजी ने उस पर दस हजार का ईनाम घोषित किया हुआ था।

सदस्य बताया जा रहा है। एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 30 नवंबर तक पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर सौंप दिया गया।

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल ने बताया कि एसओजी थाने में दर्ज प्रकरण में जांच के दौरान सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी श्रीराम विश्नोई उर्फ अतुल विश्नोई (28) निवासी भीनमाल जिला जालौर ने दो अभ्यर्थियों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

टाटा ग्रुप के कंट्रोल को लेकर झगड़े कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस मुद्दे पर काफी झड़पें हुई हैं

हालांकि, इस बार स्थिति काफी जटिल है, पर, फिर भी अंततोगत्वा मालिकों की ही चलेगी तथा "प्रौफैशनल्स" को जाना ही पड़ेगा, पर, देश के शीर्षस्थ औद्योगिक समूह को भी काफी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई होने तक कहीं टाटा ग्रुप ज्यादा ही नहीं लड़खड़ा जाए

- इस झगड़े की जड़ में कहीं न कहीं, रतन टाटा स्वयं भी जिम्मेवार हैं। उन्होंने अपने रिश्ते में सौतेले भाई नोएल टाटा को कभी महत्वपूर्ण पद पर नहीं बैठने दिया था और अब नोएल टाटा व उनकी संतानें, इस ग्रुप पर अपना नियंत्रण बनाना चाहती हैं।
- जब, रतन टाटा को इस ग्रुप के हैड के रूप में बिठाया गया था तो पुराने दिग्गज व प्रौफैशनल, जो टाटा समूह की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ चला रहे थे, ने इस नई व्यवस्था का विरोध किया था तथा रतन टाटा इस समूह पर पूर्ण कंट्रोल तब ही कर पाए थे, जब पुराने दिग्गज रिटायर हो गए।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह पर नियंत्रण हासिल करने के लिए चल रही लड़ाई कभी देश के सबसे सम्मानित औद्योगिक घरानों में शामिल रहे टाटा समूह के भविष्य को नुकसान पहुंचा रही है।

यह लड़ाई मूल रूप से टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा और टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के प्रमुख एन. चंद्रशेखरन के बीच है। टाटा संस इस ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, जिसके पास टाटा समूह की दर्जनों कंपनियों में हिस्सेदारी है।

फिलहाल एन. चंद्रशेखरन को टाटा संस के चेयरमैन के रूप में दोबारा नियुक्त किए जाने को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। टाटा संस मुख्य होल्डिंग कंपनी है, जिसकी विभिन्न कंपनियों में हिस्सेदारी है। टाटा परिवार से जुड़े नोएल टाटा चाहते हैं कि नियंत्रण फिर से परिवार के हाथों में आए और चंद्रशेखरन अपना पद छोड़ दें।

एक तरह से देखा जाए तो उत्तराधिकार की यह लड़ाई और नियंत्रण वापस हासिल करने की कोशिश टाटा समूह के लिए नई बात नहीं है। जब जेआरडी टाटा के अचानक निधन के बाद रतन टाटा को समूह का प्रमुख बनाया गया था, तब टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स और टाटा टैटली जैसी कंपनियों के कई प्रमुखों ने विद्रोह कर दिया था। टाटा टैटली विभिन्न खाद्य कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती थी।

उन्होंने अपनी इकाई का नियंत्रण ग्रुप की उस होल्डिंग कंपनी को सौंपने से इनकार कर दिया था, जो उस समय रतन टाटा के नेतृत्व में थी। काफी समय बाद ही समूह की कंपनियों के शक्तिशाली प्रमुखों, जो अपने आप में किसी साम्राज्य की तरह थे, को धीरे-धीरे हटाया जा सका और रतन टाटा को पूरा नियंत्रण मिल पाया।

हालांकि, इस नुकसान पहुंचाने वाली लड़ाई से भारत का सबसे विविध मैनुफैक्चरिंग दिग्गज समूह बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इन कंपनियों के बेहद जटिल कारोबार को सही दिशा देने के लिए वर्षों की योजना और बहुत बारीकी से काम करने की जरूरत होती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय कॉरपोरेट समूहों में टाटा समूह की एक अलग पहचान है, क्योंकि इसकी कंपनियां ही मुख्य रूप से भारतीय उद्योगों में मैनुफैक्चरिंग इकाइयाँ हैं। घरेलू मैनुफैक्चरिंग के मामले में भारत पिछड़ा हुआ है और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

घर के बाहर धूप सेक रहे बुजुर्ग को कार ने कुचला

जयपुर, 27 नवम्बर। जवाहर नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने घर के बाहर कुर्सी पर बैठकर धूप सेक रहे एक बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद कार ने सड़क किनारे खड़े एक ठेले को भी जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से ठेला

- घायल मोहनलाल की एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

करीब 10 फीट दूर जाकर पलट गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक का पीछा किया, लेकिन भीड़ को इकट्ठा होते देखकर चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शुक्रवार दोपहर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

थानाधिकारी सरला यादव ने बताया कि हादसे में मोहन लाल (66) पुत्र हंसराज निवासी सिंधी कॉलोनी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)